



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1681]
No. 1681]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 20, 2009/आश्विन 28, 1931
NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 20, 2009/ASVINA 28, 1931

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर, 2009

का.आ. 2636(अ).—यतः, मै. आन्ध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो आन्ध्र प्रदेश राज्य में एक सरकारी संगठन है, ने आन्ध्र प्रदेश राज्य के जीनोम चेली, ग्राम लालगडी मलकापेट, मंडल शमीरपेट, जिला रंगा रेड्डी में जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र हेतु एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया है;

और, यतः, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य संबंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है और उसने उपर्युक्त विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन के विकास, प्रचालन एवं रख-रखाव हेतु उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (10) के अंतर्गत दिनांक 14 जुलाई, 2009 को अनुमोदन पत्र प्रदान कर दिया है;

अतः, अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में :—

(i) केन्द्र सरकार, एतद्वारा निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्या एवं क्षेत्र को एक विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

तालिका

क्र.सं.	ग्राम का नाम	सर्वेक्षण संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	लालगडी मलकापेट	101 पी	11.33
2.		119	3.31
3.		120	5.00
4.		121 पी	0.80
	कुल		20.44 हेक्टेयर

(ii) केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 14 के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन के लिए एक समिति, जिसे अनुमोदन समिति कहा जाएगा, गठित करती है, जिसके अध्यक्ष और सदस्य निम्नानुसार हैं, अर्थात् :—

- विशेष आर्थिक जोन का विकास —अध्यक्ष, पदेन आयुक्त
- निदेशक अथवा उप-सचिव, भारत सरकार, —सदस्य, पदेन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग या उसका नामिती जिसका स्तर अवर सचिव, भारत सरकार से कम नहीं होगा
- विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाला क्षेत्रीय संयुक्त विदेश व्यापार महानिदेशक —सदस्य, पदेन
- विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाले सीमा-शुल्क आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त अथवा उनका नामिती जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा —सदस्य, पदेन

5. विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाले आयकर आयुक्त अथवा उसका नामिती जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा —सदस्य, पदेन
6. निदेशक (बैंकिंग), वित्त मंत्रालय, बैंकिंग प्रभाग, भारत सरकार —सदस्य, पदेन
7. आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले दो अधिकारी जिनका स्तर संयुक्त सचिव से कम नहीं होगा —सदस्य, पदेन
8. मै. आन्ध्रा प्रदेश इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर कार्पोरेशन लि., (जोन के विकासकर्ता) का प्रतिनिधि —विशेष आमंत्रिती

(iii) केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, दिनांक 20 अक्टूबर, 2009 को उस तारीख के रूप में निर्धारित करती है, जिस तारीख से उक्त क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन को सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 के अंतर्गत अंतर्देशीय कंटेनर डिपो माना जाएगा।

[फा. सं. 1/23/2009-एसईजेड]

अनिल मुकीम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th October, 2009

S.O. 2636(E).—Whereas, M/s. Andhra Pradesh Industrial Infrastructure Corporation Limited, a State Government Organisation in the State of Andhra Pradesh, has proposed under Section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005) (hereinafter referred to as the said Act), to set up a sector specific Special Economic Zone for biotechnology sector at Genome Valley, Village Lalgadi Malakpet, Mandal Shameerpet, District Ranga Reddy in the State of Andhra Pradesh;

And whereas, the Central Government is satisfied that requirements under sub-section (8) of Section 3 of the said Act, and other related requirements are fulfilled and it has granted letter of approval under sub-section (10) of Section 3 of the said Act for development, operation and maintenance of the above Special Economic Zone on the 14th July, 2009;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006 :

(i) the Central Government hereby notifies the following area with Survey numbers given below in the table, as a Special Economic Zone, namely :—

TABLE

Sl. No.	Name of the Village	Survey Number	Area (in Hectares)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Lalgadi Malakpet	101P	11.33
2.		119	3.31
3.		120	5.00
4.		121P	0.80
Total			20.44 hectares

(ii) The Central Government hereby also constitutes a Committee to be called the Approval Committee for the above sector specific Special Economic Zone for the purposes of Section 14 of the said Act consisting of the following Chairperson and Members, namely :—

1. Development Commissioner of the Special Economic Zone —Chairperson ex-officio
2. Director or Deputy Secretary to the Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce or his nominee not below the rank of Under Secretary to the Government of India —Member, ex-officio
3. Zonal Joint Director General of Foreign Trade, having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone —Member, ex-officio
4. Commissioner of Customs or Central Excise having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone or his nominee not below the rank of Joint Commissioner —Member, ex-officio
5. Commissioner of Income Tax having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone or his nominee not below the rank of Joint Commissioner —Member, ex-officio
6. Director (Banking) in the Ministry of Finance Banking Division, Government of India —Member, ex-officio
7. Two officers, not below the rank of Joint Secretary, to be nominated by the Government of Andhra Pradesh —Members, ex-officio
8. Representative of M/s. Andhra Pradesh Industrial Infrastructure Corporation Ltd. (Developer of Zone) —Special Invitee

(iii) the Central Government hereby also appoints the 20th day of October, 2009 as the date from which the above sector specific Special Economic Zone shall be deemed to be Inland Container Depot under Section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).

[F. No. 1/23/2009-SEZ]

ANIL MUKIM, Jt. Secy.